करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अक्तूबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **5**

- रुद्रपुर में उत्तराखंड के सबसे ऊँचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण 5
- राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार 5
- अन्नोत्सव कार्यक्रम 5
- ऋषिकेश एम्स में इनविट्रो फर्टिलाइज़ेशन (I.V.F.) सुविधा का शुभारंभ 6
- आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ 6
- अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ 6
- पर्वतारोहियों को रिस्टबैंड ट्रैकर मुहैया कराएगा उत्तराखंड 7
- 'प्रीतम भरतवाण जागर, ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी' 7
- सैलून अकादमी 8
- उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष 8
- यूपीटीटीआई के विशेषज्ञों ने पराबैंगनी किरणों से बेअसर कपड़ा बनाया 9

नोट :

- उत्तराखंड ने समय से पहले हासिल किया कोविड-19 वैक्सीनेशन लक्ष्य 9
- सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार 10
- सुरभि वाटिका (एरोमेटिक गार्डन) 10
- चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिये अभियान शुरू 10
- 'मुख्यमंत्री स्वरोज़गार नैनो योजना' 11
- 'मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना' 11
- उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण फैसले 12

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तराखंड

रुद्रपुर में उत्तराखंड के सबसे ऊँचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 2 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊँचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ बटन दबाकर 181 फीट ऊँचे तिरंगे को फहराया। इसके लिये विधायक निधि से 28 लाख रुपए खर्च किये गए।
- इस तिरंगे झंडे को ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से स्टार सेल्स कंपनी ने 47 दिनों में बनवाया है। इसके लिये कोलकाता से मटैरियल मँगवाया गया।
- इस तिरंगे झंडे का स्तंभ 51 मीटर ऊँचा है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई 36×54 फीट है। इसके निर्माण में 100 प्रतिशत पॉलिस्टर कपड़े का प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देहरादून निवासी आशु सात्विका गोयल को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार ऑल इंडिया बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आशु सात्विका गोयल को उनके सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किये गए कार्यों के लिये प्रदान किया गया है।
- आशु सात्विका गोयल एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, कलात्मक प्रशिक्षिका एवं अभिनेत्री हैं। ये देहरादून में आयोजित रंग हिमालय उत्सव की सह-संस्थापक और नई सभ्यता बनाने के लिये ग्लोबल यूथ नेटवर्क की सदस्य भी हैं।
- आशु सात्विका ने वैश्विक मुद्दों पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया है तथा भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना के साथ-साथ एक चित्रकार भी हैं।

अन्नोत्सव कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- 11 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह लाभार्थियों को राशन किट वितरित करते हुए 'अन्नोत्सव कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'अन्नोत्सव कार्यक्रम', 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत प्रारंभ किया गया महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को खाद्य एवं सम्मान प्रदान करना है।

नोट :

- राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे इस कार्यक्रम के तहत राज्य के गरीब लाभार्थियों को 14 लाख राशन किट्स उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से वितरित की जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिये वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को एन.एफ.एस.ए. (NFSA) के अंतर्गत मिलने वाले 5 किग्रा. अनुदानित अनाज़ के अतिरिक्त 5 किग्रा. मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।

ऋषिकेश एम्स में इनविट्रो फर्टिलाइज़ेशन (I.V.F.) सुविधा का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 11 अक्टूबर, 2021 को ऋषिकेश एम्स के निदेशक डॉ. अरविंद राजवंशी द्वारा एम्स के गाइनेकोलॉजी विभाग में आईवीएफ (I.V.F.) केंद्र का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स उत्तराखंड राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहाँ इनविट्रो फर्टिलाइज़ेशन की सुविधा उपलब्ध है।
- एम्स ऋषिकेश यह सुविधा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष तक की महिलाओं और 50 वर्ष तक की आयु के पुरुषों के लिये प्रदान करेगा।
- उल्लेखनीय है कि आईवीएफ (I.V.F.) एक सहायक प्रजनन तकनीक है, जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला में किसी मादा के अंडाशय से प्राप्त अंडों का संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त निषेचित अंडे को मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से पैदा हुए बच्चों को ही 'टेस्ट ट्यूब बेबी' कहा जाता है।
- आईवीएफ (I.V.F.) तकनीक का जनक रॉबर्ट एडवर्ड को माना जाता है।

आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 12 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- डीबीटी के माध्यम से 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव में किये गए कर्त्तव्य पालन के लिये यह प्रोत्साहन राशि 1 हज़ार रुपए प्रति कर्मी डीबीटी के द्वारा प्रदान की गई।
- इसके अतिरिक्त सितंबर माह में की गई घोषणा के अनुसार 5 माह तक 2 हज़ार रुपए प्रति आंगनबाड़ी कर्मी को प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई।

अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 12 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अन्नोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 1 माह में 14 लाख राशन के बैग (नि:शुल्क) वितरित किये जाएंगे।
- इसके साथ इस कार्यक्रम में ही संपूर्ण माह राज्य की समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को अप्रैल माह से नवंबर माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा. खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) तथा 1 किग्रा. दाल का प्रति कार्ड नि:शुल्क वितरण किया गया।
- इसी प्रकार वर्ष 2021 में अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवंबर तक कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा. खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि राज्य में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत अगस्त 2020 से राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्वतारोहियों को रिस्टबैंड ट्रैकर मुहैया कराएगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

- 14 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने राज्य सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स के लिये रिस्टबैंड प्रदान करने का आदेश दिया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स को रिस्टबैंड प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि आपदा या दुर्घटना के समय उपग्रहों और अन्य साधनों की मदद से उनका पता लगाया जा सके।
- इसके साथ ही संधू ने संबंधित अधिकारियों को पर्यटन को गति देने के लिये कनेक्टिविटी पर काम करने और हेलीपैड तथा हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।
- उन्होंने ऐसे क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस करने का निर्देश दिया, जहाँ पर्यटन संबंधी गतिविधियों की काफी संभावनाएँ हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्गों पर पर्यटकों के लिये हर 20-30 किलोमीटर पर पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

'प्रीतम भरतवाण जागर, ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी'

चर्चा में क्यों ?

- 17 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक संस्कृति, जागर, ढोल सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से देहरादून नालापानी चौक में 'प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस अकादमी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
- इस अकादमी में लोक संगीत, पारंपरिक ढोल दमाऊ, हुड़का डोर आदि में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं और शोधार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे इन्हें उत्तराखंडी लोक संस्कृति को समझने एवं जानने का अवसर प्राप्त होगा और उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित किया जा सकेगा।
- इस अवसर पर ढोल कला विरासत को सँजोने वाले 107 वर्षीय ढोल सागर ज्ञाता शेरदास व 81 वर्षीय कलम दास सहित अन्य कलावंतों को सम्मानित किया गया।

- गौरतलब है कि इस अकादमी के संचालक पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण हैं। प्रीतम भरतवाण का जन्म देहरादून ज़िले के सिला गाँव में हुआ था। वे उत्तराखंड के एक लोक गायक कलाकार हैं। जागर, लोकगीत, पवांडा और घुयांल गाने के साथ ही ढोल, दमाऊ, हुड़का और डौर उत्तराखंडी वाद्य यंत्र थकुली बजाने में भी महारत हासिल कर चुके हैं।
- इन्हें भारत सरकार ने जागर गायन के लिये वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

सैलून अकादमी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में विधायक विनोद चमोली और एफ सैलून अकादमी की सीईओ प्राची कौशिक ने देहरादून में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैशन और जीवन शैली प्रसारण टेलीविज़न चैनल फैशन टीवी (FTV) की एफ सैलून अकादमी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- FTV सैलून अकादमी, देहरादून के मालिक, तुषार प्रताप सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य एफ सैलून अकादमी के माध्यम से फैशन उद्योग को अपने सबसे असाधारण गुणवत्ता वाले पेशेवरों के साथ प्रस्तुत करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- FTV सैलून अकादमी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है तथा इन मानकों के अनुरूप ही उत्तराखंड के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- FTV सैलून अकादमी के सीईओ प्राची कौशिक ने कहा कि पूरे भारत में अकादमी की 500+ फ्रेंचाइजी स्थापित किया जाएगा, जिसमें छात्र 100 से अधिक ब्यूटी कोर्स कर सकते हैं।
- यह अकादमी न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेशेवरों के उत्पादन तक सीमित है, बल्कि प्रति वर्ष 14 मिलियन नौकरियों का सृजन करके भारतीय बाज़ार में क्रांति लाएगी।
- उन्होंने कहा कि हम छात्रवृत्ति प्रदान करके समाज के कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगों, गृहिणियों आदि के उत्थान के लिये विभिन्न सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़ने की भी योजना बना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

- 18 अक्तूबर, 2021 को समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने इकलौते प्रतिद्वंद्वी नरेंद्र सिंह वर्मा को हराया।

प्रमुख बिंदु

- उपसभापति के चुनाव के लिये मतदान सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू हुआ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने शाम 4 बजे परिणाम की घोषणा की।
- विधानसभा की कुल 403 सदस्यों की तुलना में 368 विधायकों ने मतदान किया, जिनमें से चार मत अवैध घोषित किये गए। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि नरेंद्र सिंह वर्मा को सिर्फ 60 वोट मिले।
- कॉन्ग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि दोनों दलों के बागी विधायकों ने भाजपा या समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने चुनाव का विरोध किया और काला बिल्ला पहना।
- सत्तारूढ़ भाजपा ने उपाध्यक्ष पद के लिये समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल न होने के बावजूद मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी इस पद के लिये अपने उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा का नामांकन दाखिल किया था।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान (17वीं) विधानसभा में भाजपा की कुल 304 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के 49 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 16, अपना दल (सोनेलाल) के 9, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के 7 तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक हैं। 3 निर्दलीय, 2 असंबद्ध सदस्य तथा 2 अन्य सदस्य हैं जबकि 7 सीटें खाली हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक मनोनीत सदस्य भी है।

नोट :

यूपीटीटीआई के विशेषज्ञों ने पराबैंगनी किरणों से बेअसर कपड़ा बनाया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (UPTTI) के विशेषज्ञों ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है, जिस पर धूप एवं पराबैंगनी किरणों का कोई असर नहीं होता।

प्रमुख बिंदु

- यह कपड़ा दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने वाले पौधे से प्राप्त होने वाले बायो-पॉलीमर लिगनिन से तैयार नाइलॉन से बना है।
- यह कपड़ा लोगों को तेज़ गर्मी से भी राहत देगा और शरीर के लिये भी आरामदायक होगा।
- UPTTI ने इस रिसर्च को पोलैंड के जर्नल में प्रकाशित करवाया तथा इस तकनीक के पेटेंट के लिये भी आवेदन किया है।
- उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका में बायो-पॉलीमर लिगनिन का उपयोग भवन और सड़क निर्माण में किया जाता है लेकिन UPTTI के विशेषज्ञों ने इसका उपयोग पहली बार टेक्सटाइल में किया है।
- यह तकनीक कपड़ों में उपयोग हो रही डाई से 1/3 गुना सस्ती है। डाई मानव शरीर को भी हानि पहुँचा सकती है लेकिन इस तकनीक से बने कपड़े मानव उपयोग के लिये पूर्णत: सुरक्षित हैं।
- इस तकनीक को प्रो. अरुण सिंह गंगवार ने प्रो. प्रशांत विश्नोई के सहयोग से विकसित किया है।
- ज्ञातव्य है कि पराबैंगनी किरणों से सन बर्न, शरीर में दाने, स्किन कैंसर एवं अन्य अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस तकनीक के विकास से ये समस्याएँ कम की जा सकती हैं।
- प्रो. गंगवार के अनुसार, कपड़े की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर (UVPF) पर निर्भर रहती है। UVPF 15 से 24 के बीच अच्छा, 25 से 39 के बीच बहुत अच्छा एवं 40 से 45 के बीच श्रेष्ठ माना जाता है।

उत्तराखंड ने समय से पहले हासिल किया कोविड-19 वैक्सीनेशन लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश ने 18 वर्ष की आयु से अधिक की योग्य आबादी को कोविड-19 के टीके की पहली खुराक देने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक मंज़ूरी मिलते ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर देगी।
- धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 16 जनवरी, 2021 को टीकाकरण शुरू हुआ था, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के कुल 77,29,466 लोगों को टीका लगाया जाना था।
- उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया और उनके बाद क्रमश: फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या, 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की आयु वाली जनसंख्या और फिर सभी 18 वर्ष से अधिक की आयु वाली आबादी को टीके लगाए गए।
- धामी ने बताया कि 16 अक्तूबर तक राज्य के 99.6 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों, 9.2 फीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 से अधिक आबादी में से 96.1 फीसदी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।
- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, विरोधाभासी हितग्राहियों (गंभीर बीमारी, खून को पतला करने वाली दवाएँ लेने वाली) और टीकाकरण कराने में रुचि नहीं लेने वालों के अलावा सभी पात्र लोगों को पहली खुराक का टीका लगाया गया है।

नोट :

सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एग्रीकल्चर टू ग्रुप द्वारा आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के कृषि और बागवानी मंत्री सुबोध उनियाल को देश में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड ने किसानों की आय बढ़ाने के लिये एकीकृत कृषि का मॉडल अपनाया है। राज्य सरकार 20,000 मशरूम उत्पादकों को बढ़ावा दे रही है और ज़िला योजना के तहत 40 प्रतिशत धनराशि कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के लिये आरक्षित की गई है। इससे राज्य में पॉली हाउस निर्माण और उच्च घनत्व वाले फल वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल रहा है।
- इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों को पाँच लाख रुपए का ब्याजमुक्त ऋण और तीन लाख रुपए का कम ब्याज वाला ऋण प्रदान कर रही है।
- उनियाल ने कहा कि राज्य ने अधिक उपज देने वाले फलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है, किसानों को गैर-मौसमी सब्जियाँ उगाने के लिये प्रोत्साहित किया है और नर्सरी अधिनियम को लागू किया है।
- ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है, जिसने नर्सरी एक्ट के तहत छह माह की कैद का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देकर 'उत्तराखंड सेब' का एक अलग ब्रांड विकसित किया है।

सुरभि वाटिका (एरोमेटिक गार्डन)

चर्चा में क्यों ?

- 24 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में लालकुआँ के वन अनुसंधान केंद्र में महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकान संस्था की संचालिका बीणा राव और प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से देश की पहली सुरभि वाटिका (एरोमेटिक गार्डन) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य वन संरक्षक संजीव ने बताया कि तीन एकड़ क्षेत्रफल में इस वाटिका को तीन साल में तैयार किया गया है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से 140 सगंध प्रजाति के पौधों लगाया गया है, जिसके चलते यह देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया है।
- इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में यह मददगार साबित हो सकेगी। वाटिका को नौ हिस्सों में तैयार किया गया है।
- यहाँ कई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। भविष्य में सगंध प्रजातियों के पौधों को लालकुआँ और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बाँटा जाएगा।
- अनुसंधान केंद्र स्थित फाइकस गॉर्डन से भी क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि देश के दूसरे नंबर के इस फाइकस गार्डन में 121 फाइकस प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं।

चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिये अभियान शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 25 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिये 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह अभियान उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर शुरू किया है।
- इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिये 1200 किमी. से अधिक का सफर तय करेगा। इस दल द्वारा यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा।
- 25 सदस्यीय दल पुराने चारधाम मार्ग और शीतकालीन चारधाम मार्ग को खोजने का काम करेगा।
- उल्लेखनीय है कि यह पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस अभियान से उत्तराखंड में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।

‘मुख्यमंत्री स्वरोज़गार नैनो योजना’

चर्चा में क्यों ?

- 26 अक्टूबर, 2021 को राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मज़बूत और सशक्त बनाने की दिशा में ‘मुख्यमंत्री स्वरोज़गार नैनो योजना’ का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पूर्व के शासनादेश में संशोधन करते हुए इस योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दिया गया है।
- योजना में इस संशोधन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी फल, सब्जी रेहड़ी लगाने वाले, चाय ठेला वाले, दर्ज़ी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर आदि छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रदेश में 5 श्रेणियाँ क्रमश: A, B, B+ C एवं D निर्धारित की गई हैं।
- श्रेणी ए सामान्य अभ्यर्थियों को (परियोजना की लागत पर) 35 प्रतिशत, अधिकतम 17,500 हज़ार रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/ महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत, अधिकतम 20 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार श्रेणी बी और बी+ में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 30 प्रतिशत और अधिकतम 15,000 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ‘35 प्रतिशत, अधिकतम 17,500 रुपए’ का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार श्रेणी सी और डी हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 25 प्रतिशत और अधिकतम 12,500 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ‘30 प्रतिशत अधिकतम, 15,000 रुपए’ का अनुदान दिया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’ का पुन: शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को दूध वितरित कर योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का पुन: शुभारंभ होने से बच्चों के विकास एवं उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माँ का आँचल बच्चे का धूपछाँव से बचाव करता है, उसी प्रकार ‘आँचल अमृत योजना’ बच्चों में कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होगा।

- उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, इससे यह योजना भी कुछ समय तक प्रभावित रही, जिसे अब पुन: शुरू कर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन नि:शुल्क फोर्टीफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा।
- इस योजना से प्रदेश के 1 लाख 70 बच्चों को लाभ मिलेगा, साथ ही बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत 1 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 85 हज़ार धात्री माताओं को लाभ मिल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 7 मार्च, 2019 को 'मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना' का शुभारंभ किया गया था।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण फैसले

चर्चा में क्यों?

- 28 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं के लाभ से जुड़े कई पैसले लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल की बैठक में 25 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई, जिनमें से 24 के संदर्भ में पैसले लिये गए, जबकि एक प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया गया।
- बैठक में लिये गए कुछ महत्त्वपूर्ण पैसले हैं-
  - मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये गोल्डन कार्ड योजना के पैकेज तय करने में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की प्रचलित दरें लागू होंगी।
  - मंत्रिमंडल ने एमबीबीएस कोर्स की फीस भी कम कर दी है, जो छात्र राज्य सरकार के साथ ब्रॉण्ड में प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें केवल 1.45 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना होगा। फिलहाल यह शुल्क 4 लाख रुपए है।
  - राज्य में कार्यरत् आशा फैसिलिटेटरों का प्रोत्साहन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है।
  - मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बोनस देने का भी फैसला किया।
  - मंत्रिमंडल ने 29 और 30 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने की भी मंज़ूरी दी।
  - मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को अब हफ्ते में दो दिन फल, मेवाएँ और अंडे वितरित किये जाएंगे।
  - वीरचंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना नियमावली 2002 में संशोधन करते हुए सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण किया गया है।
  - पेयजल व सीवर के बिलों पर बड़ी राहत देते हुए मार्च 2022 तक लेट फीस न लेने की घोषणा की गई है।
  - उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजरों को भी मिलेगा प्रमोशन, सेवा नियमावली को मंज़ूरी।